Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- प्रदेश की दो महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023 के लिये चयन 3
- अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एंबुलेंस सेवा 3
- उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर बढ़ाई सब्सिडी 4
- प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 4
- महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और इन्हें रोकने वाले होंगे सम्मानित 5
- उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मिली मंजूरी 5
- उत्तराखंड में तीन दिवसीय वसंतोत्सव शुरू 5
- रुद्रप्रयाग और टिहरी सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित ज़िले करार 6
- उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में खुलेगी कैथ लैब 8
- मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोज़गार योजना 9
- सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन 9
- उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल 10
- उत्तराखंड के वीर नारियाँ और वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिक रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त में सफर 10
- आईआईटी रुड़की ने खोजा अनोखा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल 11
- उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति - 2023 11
- चिन्यालीसौड़ में वायुसेना का तीन दिवसीय अभ्यास शुरू 12
- उत्तराखंड बजट- 2023-2024 12
- चमोली की मानसी नेगी ने 20 किमी. वॉक रेस में जीता स्वर्ण पदक 14
- उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी 15
- परमजीत ने रेस वॉक में ओलंपिक 2024 के लिये किया क्वालीफाई 15
- उत्तराखंड में द्रोणाचार्य, खेल रत्न और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिये नाम तय 16
- उत्तराखंड कैबिनेट ने आबकारी नीति 2023-24 को दी मंजूरी 17
- केंद्रीय मंत्री ने किया देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन 17
- सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक 18
- 'रेट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक' 20
- मुख्यमंत्री ने की कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ 20
- जल जीवन मिशन के लिये प्रदेश को मिले 403 करोड़ 21
- मुख्यमंत्री ने प्रदान किये उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 22
- पहली बार यात्रा मार्गों पर लगेंगे 50 हेल्थ एटीएम 23
- उत्तराखंड में जल्द ही गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिग होम की सुविधा 23
- प्रदेश में आभा आईडी बनाने में देहरादून ज़िला अव्वल 24
- उत्तराखंड में पेपरलेस होगी विधानसभा 25
- जी-20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक रामनगर में आयोजित हुई 26
- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस) का कंप्यूटरीकरण सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया 27

नोट :

उत्तराखंड

प्रदेश की दो महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023 के लिये चयन

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनपद बागेश्वर से सरपंच कविता देवी व देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को अपने-अपने गाँवों को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान देने के लिये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से आगामी चार मार्च को विज्ञान भवन, नयी दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023' से सम्मानित किया जाएगा।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के तहत चार मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनो महिला सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य की महिला सरपंचों को यह सम्मान मिलना प्रदेशवासियों विशेषकर यहाँ की महिलाओं के लिये गौरव का विषय है।
- यह सम्मान उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के असाधारण योगदान का सम्मान है। यह सम्मान उन सभी लोगों को प्रेरित करेगा जो अपने गाँवों को स्वच्छ बनाने और गाँवों में जल संरक्षण के लिये कार्य कर रहे हैं। गाँवों को स्वच्छ बनाने, ओडीएफ प्लस मॉडल गाँवों के निर्माण, हर घर जल मिशन व जल संरक्षण में ग्राम प्रधानों एवं सरपंचों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- उत्तराखंड में महिला ग्राम प्रधान, महिला सरपंच, महिला स्वच्छाग्रही, महिला स्वयं सहायता समूह, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता बहनें धरातल स्तर पर अपनी प्रभावी नेतृत्व क्षमता और कुशल प्रबंधन के माध्यम से राज्य के विकास में असाधारण योगदान दे रही हैं।

अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एंबुलेंस सेवा

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एम्स ऋषिकेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश का पहला हेली एंबुलेंस पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने हेली एबुलेंस के संचालन के लिये एक कंपनी से अनुबंध किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार साझा रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हेली एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगी।
- केंद्र और उत्तराखंड सरकार 50-50 फीसदी की साझेधारी में हेली एंबुलेंस सेवा का संचालन करेगी। अनुबंधित कंपनी एक महीने में 45 घायलों और मरीजों को निशुल्क हेली एंबुलेंस उपलब्ध कराएगी। हेली एंबुलेंस पूरे उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के 100 किमी. के दायरे में सेवा मुहैया कराएगी।
- अनुबंधित कंपनी एम्स को सिंगल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराएगी। इसमें चिकित्सा संसाधन भी कंपनी लगाएगी। एम्स प्रशासन हेली एंबुलेंस के संचालन के लिये मेडिकल मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) तैयार कर रहा है। हेली एंबुलेंस का पहले ट्रायल रन होगा। एम्स प्रशासन से हरी झंडी मिलने के बाद सेवा शुरू हो जाएगी।
- हेली एंबुलेंस सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब तक दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर बीमार यात्रियों को एयर लिफ्ट कर एम्स लाया जाता था। लेकिन, अब हेली एंबुलेंस इन्हें एम्स पहुँचाएगी।
- ऋषिकेश एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने कहा कि हेली एंबुलेंस सेवा से पर्वतीय और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर घायलों और मरीजों को समय पर उपचार मिल पाएगा। प्रोजेक्ट की सफलता से देश के अन्य राज्यों में भी हेली एंबुलेंस सेवा का रास्ता खुलेगा।

नोट :

उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर बढ़ाई सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना' के तहत युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिये दिशा-निर्देश बदल दिये गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना' के तहत प्रदेश में 10 हज़ार सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लगाने वालों को 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान था। योजना के तहत 20 से 25 किलोवाट तक के ही प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे।
- इस योजना में युवाओं ने उत्साह नहीं दिखाया, जिसकी वजह से लक्ष्य के सापेक्ष केवल 120 प्रोजेक्ट ही लग पाए। इसीलिये अब सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है।
- नई नियमावली के तहत अब सब्सिडी 15 से 40 प्रतिशत तक मिलेगी। 20 से 25 किलोवाट के स्थान पर 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट के परियोजना संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
- युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिये सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लगाने में आने वाली लागत की दर भी 40 हज़ार रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए प्रति किलोवाट कर दी है। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना में युवाओं का रुझान बढ़ेगा।

प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये राज्य के 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये इसमें बेसिक के 10, माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान से एक शिक्षक शामिल है।
- शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा में राज्य के पौड़ी ज़िले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटलमंडा की प्रधानाध्यापक आशा बुड़ाकोटी, उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय बड़ेथी के प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुकसाल, देहरादून ज़िले के जूनियर हाईस्कूल डोईवाला के सहायक अध्यापक ऊषा गौड़, हरिद्वार ज़िले के जूनियर हाईस्कूल रोशनाबाद के प्रधानाध्यापक संजय कुमार, टिहरी ज़िले के प्राथमिक विद्यालय उलाणा के प्रधानाध्यापक उत्तम सिंह राणा, चंपावत ज़िले के जूनियर हाईस्कूल बिसारी के सहायक अध्यापक रवीश चंद पचौली को पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है।
- इनके अलावा बागेश्वर ज़िले के जूनियर हाईस्कूल पिंगलौ के सहायक अध्यापक सुरेश चंद्र सती, पिथौरागढ़ ज़िले के प्राथमिक विद्यालय भट्टी गाँव के प्रधानाध्यापक गंगा आर्या, अल्मोड़ा ज़िले के जूनियर हाईस्कूल पौड़ा कोठार के सहायक अध्यापक यशोदा कांडपाल, नैनीताल ज़िले के प्राथमिक विद्यालय धुलई के प्रधानाध्यापक डॉ. आशा बिष्ट को पुरस्कृत किया जाएगा।
- माध्यमिक स्तर पर उत्तरकाशी ज़िले में इंटर कालेज कीर्ति के लोकेंद्रपाल सिंह, देहरादून ज़िले के जीआईसी क्वानू के प्रवक्ता संजय कुमार मौर्य, पिथौरागढ़ ज़िले के जीआईसी बड़ावे की सहायक अध्यापिका दमयंती, बागेश्वर ज़िले के जीआईसी कांडा के प्रवक्ता त्रिभुवन चंद, अल्मोड़ा ज़िले के जीआईसी रयालीधार के प्रवक्ता प्रभाकर जोशी, ऊधमसिंह नगर ज़िले के राजकीय गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा के प्रवक्ता निर्मल कुमार का पुरस्कार के लिये चयन किया गया है।
- इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान से ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह धपोला को पुरस्कृत किया जाएगा।

नोट :

महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और इन्हें रोकने वाले होंगे सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महिला सशक्तीकरण एवं सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों के प्रति हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने एवं इसे रोकने का प्रयास करने वालों को सम्मानित करेगी।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे व्यक्ति या समूह को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा।
- इसके अलावा समाज की कुरीति, बाल विवाह की पूर्वसूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को दस हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति- पत्र दिया जाएगा।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर 'अपनी वाणी' की शुरुआत की एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया।
- उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने एवं सामाजिक सरोकारों के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- इस अवसर पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये विभाग की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। एकल महिलाओं को भी सशक्त करने की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिये योजना शुरू करने का संकल्प लिया है।

उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड में श्रमिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों की सेवाएँ लेने वाले प्रतिष्ठानों को अब श्रम विभाग से हर हाल में 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा।
- नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अगर अधिष्ठानों के पंजीकरण के लिये मुख्य नियोजक, श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उस आवेदन पर अधिकारी 20 दिन में निर्णय नहीं लेता है तो वह स्वत: पंजीकृत समझा जाएगा।

उत्तराखंड में तीन दिवसीय वसंतोत्सव शुरू

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजभवन परिसर में तीन दिवसीय वसंतोत्सव का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने उद्यान विभाग की ओर से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये टोल फ्री किसान हेल्प लाइन नंबर 18003135685 लांच किया।
- उन्होंने कार्यक्रम में उद्यान विभाग की पुस्तक 'शुष्क पुष्प व्यावसायिक' हस्त पुस्तिका तथा नक्षत्र वाटिका पर बनी लघु फिल्म का विमोचन किया। वहीं डाक विभाग की ओर से इस साल के लिये चयनित तिमरू के विशेष डाक आवरण का विमोचन तथा डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वसंतोत्सव लोगों को प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रोत्साहित करता है। इस महोत्सव के जरिये उत्तराखंड कृषि एवं उद्यानीकरण के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
- राजभवन में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में संस्कृति विभाग सहित स्कूली बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किये। सांस्कृतिक कलाकारों ने झूमैलो, छपेली, चांचरी, तांदी, हारुल आदि लोक नृत्य प्रस्तुत किये।
- वसंतोत्सव के आयोजन में कट फ्लावर (पारंपरिक) प्रतियोगिता में 698, कट फ्लावर (गैर पारंपरिक) श्रेणी में 191 प्रतिभागी, पॉटेड प्लांट श्रेणी(प्राइवेट नर्सरी) में 22, लूज फ्लावर श्रेणी में 42, पॉटेड प्लांट (गैर पुष्प) श्रेणी में 17, कैक्टस एवं सेकुलेंट श्रेणी में 13, हैंगिंग पॉट श्रेणी में 27, ऑन स्पॉट फोटोग्राफी में 22, लॉन श्रेणी में 17, फ्रेश पेटल रंगोली में 08 और पेंटिंग प्रतियोगिता में 946 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- इस साल शुरू की गई नई प्रतियोगिताओं, छतों पर सब्जी उत्पादन की श्रेणी में 12, बोनसाई की श्रेणी में 23, टेरेरियम की श्रेणी में 7 एवं शहद की श्रेणी में 33 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।
- 3 से 5 मार्च तक राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव के दौरान पुष्प प्रदर्शनी के साथ कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा।

रुद्रप्रयाग और टिहरी सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित ज़िले करार

चर्चा में क्यों ?

6 मार्च, 2023 को वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी) की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी ज़िले देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित ज़िले हैं।

प्रमुख बिंदु

- भू-विज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल ने बताया कि रिपोर्ट में भूस्खलन जोखिम विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार, सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 ज़िलों में उत्तराखंड के सभी 13 ज़िले शामिल हैं। इनमें रुद्रप्रयाग पहले, टिहरी दूसरे स्थान पर तथा चमोली ज़िला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है।

नोट :

- विदित है कि चमोली ज़िले का जोशीमठ शहर इन दिनों भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। वैज्ञानिक इसकी तकनीकी जांच कर खतरे को भाँप रहे हैं। बहरहाल उपग्रह से लिये गए चित्रों की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तरकाशी देश में 21वें स्थान पर है। पौड़ी गढ़वाल की 23वीं और देहरादून ज़िले की 29वीं रैंकिंग है।
- देश में सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व वाला ज़िला रुद्रप्रयाग है। यानी भूस्खलन से इस ज़िले को सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक क्षति होने का खतरा है। यही स्थिति टिहरी ज़िले की भी है। ये दोनों ज़िले भौगोलिक रूप से दूसरे ज़िलों की तुलना में छोटे हैं। इस लिहाज से भी भूस्खलन घनत्व बड़ा दिखाई दिया है।
- एटलस के मुताबिक, देश में भूस्खलन के लिहाज से सबसे अधिक जोखिम भरे पहले दो ज़िले रुद्रप्रयाग व टिहरी उत्तराखंड में हैं। तो सबसे कम संवेदनशील ज़िले हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर भी राज्य में ही हैं।
- एनआरएससी के भूस्खलन जोखिम विश्लेषण में 147 ज़िलों में हिमाचल के 11 ज़िले शामिल हैं। हिमाचल में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा मंडी ज़िले में है। प्रदेश में इस ज़िले की रैंक 16वीं है।
- हिमालयी राज्यों में शामिल जम्मू और कश्मीर के 14 ज़िले भूस्खलन जोखिम वाले ज़िलों की सूची में शामिल हैं। इनमें राजौरी देश का चौथा और पुंछ छठा सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित ज़िला है।
- 147 संवेदनशील ज़िलों की सूची में केरल के कुल 10 ज़िले हैं, जहाँ भूस्खलन से खतरा है। 10 सबसे अधिक भूस्खलन जोखिम ज़िलों की सूची में केरल के तीन ज़िले शामिल हैं।
- पूर्व वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल ने बताया कि पूरा हिमालयी क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। एनआरएसी की इस रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत अध्ययन होना चाहिये। भूस्खलन से वास्तविक नुकसान कितना है? कितनी आबादी को वह प्रभावित कर रहा है? इससे नीति नियामक यह तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह की योजना बनानी है।
- उत्तराखंड के सबसे प्रभावित ज़िले (लाल रंग में)-

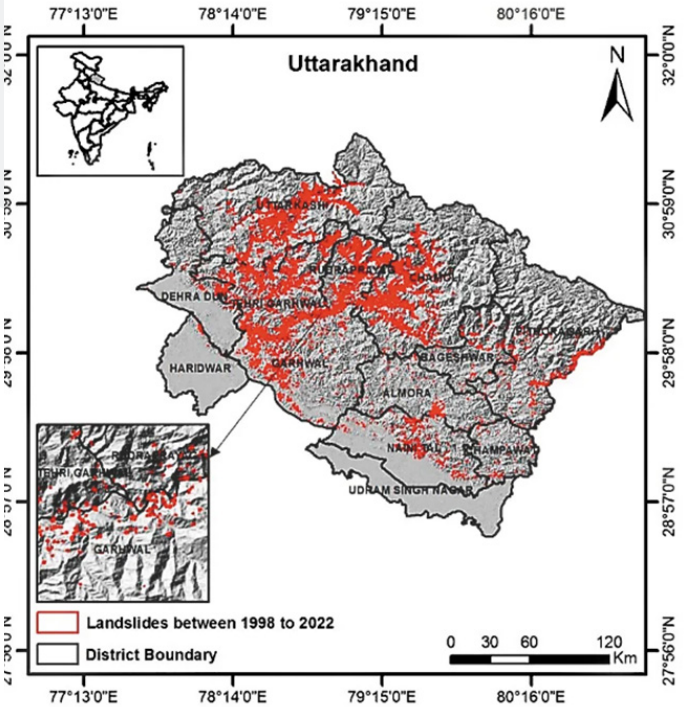

नोट :

उत्तराखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों में खुलेगी कैथ लैब

चर्चा में क्यों ?

7 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन-औषधि दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब स्थापित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश के सभी ज़िला व मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में एमआरआई व सिटी स्कैन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही टेक्नीशियन की कमी को पूरा किया जाएगा।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2022-23 में जन-औषधि के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले डॉ.पुनीत धमीजा, जन-औषधि मित्र के रूप में श्रेष्ठ कार्य करने वाले मुकुल अग्रवाल और जन-औषधि ज्योति के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वालीं कुसुम गोयल को सम्मानित किया।
- इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में जो भी जन-औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, उनमें सरकार पाँच लाख रुपए की सहायता दे रही है। 225 जन-औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं तथा राज्य को अभी 400 जन-औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य मिला है।
- उन्होंने बताया कि राज्य की सभी 670 न्याय पंचायतों में को-ऑपरेटिव सोसाइटी में एक-एक जन-औषधि केंद्र खोला जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में जन-औषधि योजना सेवा और रोज़गार दोनों का एक सशक्त माध्यम बन गई है। इस योजना से सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी बहुत लाभ हुआ है। देशभर में एक हज़ार से ज्यादा जन-औषधि केंद्र तो ऐसे हैं, जिन्हें सिर्फ महिलाएँ ही चला रही हैं। यह योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है।
- प्रदेश में अभी तक आयुष्मान योजना में केंद्र सरकार के सहयोग से 70 हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन केंद्रों में जन-सामान्य की चिकित्सा सुविधा के लिये योग, आयुर्वेद, पंचकर्म से संबंधित सभी सेवाओं के साथ-साथ लैब टेस्टिंग जैसी सुविधाओं और जन-औषधि केंद्र को भी जोड़ा गया है।

नोट :

मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोज़गार योजना

चर्चा में क्यों ?

7 मार्च, 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिये उन्हें गाँव में ही स्वरोज़गार देने हेतु 'मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोज़गार योजना' की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 'मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोज़गार योजना' के लिये न्यूनतम 25 साल से लेकर अधिकतम 45 साल तक की महिलाएँ पात्र होंगी तथा उत्तराखंड की मूल, स्थाई निवासी, एकल, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एवं तेजाब पीड़ित महिलाएँ भी इस योजना के लिये पात्र होंगी।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके लिये अभी 50 लाख रुपए का कारपस फंड बनाया गया है, जिसे बढ़ाए जाने के लिये कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
- मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पात्र महिला की मासिक आय 6000 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा वो किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर-सरकारी, सरकारी उपक्रम आदि में कार्यरत् न हो। वे राजकीय, पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो। हालाँकि कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन पाने वाली विधवा, दिव्यांग आदि महिलाएँ भी योजना के लिये पात्र होंगी।
- 'मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोज़गार योजना' में महिलाओं को 50 हज़ार से लेकर दो लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत ऋण एवं 25 प्रतिशत अनुदान धनराशि दी जाएगी, जबकि प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के तीन महीने बाद 50 प्रतिशत ऋण की वापसी की किश्त शुरू होगी।
- महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि महिलाओं के सफलतापूर्वक 12 महीने तक एक प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण की अदायगी के बाद द्वितीय किश्त के रूप में 25 प्रतिशत अनुदान की धनराशि दी जाएगी।
- एकल महिलाएँ स्वरोज़गार के लिये बागवानी, कृषि, कुक्कुट पालन, भेड़, बकरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, फल, खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।

सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन माह तक चलने वाले प्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि मेले का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- माँ पूर्णागिरि की चरणस्थली ठुलीगाड़ में हुए समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छह माह चलने वाली चारधाम यात्रा के दौरान 50 लाख श्रद्धालु दर्शनों को पहुँचते हैं। तीन माह की मेला अवधि के दौरान 35 लाख श्रद्धालु पूर्णागिरि धाम आते हैं।
- माँ पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जनपद के टनकपुर के पर्वतीय अंचल में अन्नपूर्णा छोटी के शिखर में लगभग 3000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 108 सिद्धपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर सती माता की नाभि गिरी थी।
- पूर्णागिरि को पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शारदा नदी के पास स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर अपने चमत्कारों के लिये भी खासा जाना जाता है।

नोट :

उत्तराखंड में होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल

चर्चा में क्यों ?

12 मार्च, 2023 को उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डी.के. सिंह ने बताया कि प्रदेश के हल्द्वानी में पी.टी. ऊषा की अध्यक्षता में हुई भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की बैठक में तय किया गया है कि वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छत्तीसगढ़ ने भी राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की दावेदारी की थी, लेकिन आईओए ने उत्तराखंड को मेज़बानी दी है।
- भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में देश में खेलों के विकास के अलावा अन्य प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इस दौरान राष्ट्रीय खेलों पर भी चर्चा हुई, जिसमें तय हुआ कि इस वर्ष सितंबर-अक्तूबर में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किये जाएंगे।
- आईओए ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी परखने के लिये आईओए की संयुक्त सचिव अलकनंदा अशोक को तात्कालिक रूप से नामित किया है।
- ज्ञातव्य है कि 2015 में केरल के बाद गोवा और उत्तराखंड को ये खेल कराने थे, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में आधी-अधूरी तैयारी की वजह से ये खेल 2018 से टलते रहे। 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा, 37वें छत्तीसगढ़, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को 2014 में ही आवंटित कर दिये गए थे, लेकिन गोवा ने 36वें खेल कराने से अपने हाथ पीछे खींचे और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी तैयारी अधूरी रहने से राष्ट्रीय खेल लगातार खिसकते रहे।
- विदित है कि राष्ट्रीय खेलों में लगातार हो रही देरी को देखते हुए आईओए के तत्कालीन अध्यक्ष हल्द्वानी निवासी राजीव मेहता ने भारत सरकार और गुजरात सरकार से बात करके बेहद कम समय में गुजरात में राष्ट्रीय खेल सितंबर 2022 में आयोजित करा दिये थे।

उत्तराखंड के वीर नारियाँ और वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिक रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त में सफर

चर्चा में क्यों ?

11 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की 1130 वीर नारियाँ और वीरता पुरस्कार पाने वाले 1727 सैनिक एवं पूर्व सैनिक उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं के परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर करने से इस पर जो खर्च आएगा, नियमानुसार उसका भुगतान एवं प्रतिपूर्ति सैनिक कल्याण विभाग की ओर से परिवहन निगम को किया जाएगा।
- प्रदेश के निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग को दिये आदेश में कहा गया है कि सैनिक कल्याण विभाग के आय-व्यय में नई मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था कराने के लिये समय से प्रस्ताव तैयार कर इसे शासन को उपलब्ध कराया जाए।
- गौरतलब है कि प्रदेश में सबसे अधिक 203 वीर नारियाँ (युद्ध विधवा) पिथौरागढ़ ज़िले में हैं। इसमें 185 वीर नारियाँ देश के लिये शहीद हुए सैनिकों, 17 जेसीओ और एक शहीद सैन्य अधिकारी की पत्नी हैं।
- इसके अलावा अल्मोड़ा में 82, बागेश्वर में 97, चंपावत में 32, चमोली में 115, देहरादून में 143, हरिद्वार में 13, लैंसडाउन में 150, नैनीताल में 69, पौड़ी में 70, रुद्रप्रयाग में 43, टिहरी में 63, ऊधमसिंह नगर में 40, उत्तरकाशी में 10 वीर नारियाँ हैं।
- प्रदेश में देश की सुरक्षा के लिये अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों की कमी नहीं है। राज्य में 1727 सैनिकों और पूर्व सैनिकों को महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल आदि विभिन्न वीरता पुरस्कार मिले हैं।

नोट :

आईआईटी रुड़की ने खोजा अनोखा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल

चर्चा में क्यों ?

11 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रुड़की स्थित आईआईटी के शोधकर्त्ताओं ने एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोज निकाला है, जो दवाओं के साथ इस्तेमाल किये जाने पर न केवल स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकेगा, बल्कि दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा।

प्रमुख बिंदु

- संस्थान ने इस मॉलिक्यूल को आईआईटीआर 00693 नाम दिया है। आईआईटी रुड़की के इस शोध का निष्कर्ष प्रतिष्ठित अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जर्नल एसीएस इंफेक्शियश डिजीजेज में प्रकाशित हुआ है।
- शोध करने वाली टीम में ऋषिकेश एम्स के आशीष कोठारी और बलराम उमर के अलावा चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की वर्षा गुप्ता भी शामिल हैं। आईआईटी रुड़की के महक सैनी और अमित गौरव भी टीम का हिस्सा हैं।
- शोध टीम का नेतृत्व करने वाली आईआईटी रुड़की के बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर रंजना पठानिया ने बताया कि अब अणु को एक व्यवहार चिकित्सीय एजेंट के रूप में विकसित करने के लिये काम कर रहे हैं। जल्द ही इसका क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है।
- आईआईटी के इस नए मॉलिक्यूल का ग्राम-पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया पर भी प्रभावी असर होगा। फेफड़ों, आँतों, जोड़ों और त्वचा के संक्रमण के अलावा जलने की अवस्था में फैलने वाले संक्रमण में भी यह मॉलिक्यूल अन्य एंटीबैक्टीरियल दवाओं के साथ दिये जाने पर बेहतर परिणाम देगा।
- इस नए मॉलिक्यूल से शरीर के नाजुक अंगों और त्वचा में होने वाले घातक संक्रमण के ईलाज़ के दौरान दवा के प्रतिरोध को जल्द ही खत्म किया जा सकेगा।

उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति - 2023

चर्चा में क्यों ?

13 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति (उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति - 2023) को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति - 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस प्रोजेक्ट से होगा। इनसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
- नई सौर ऊर्जा नीति के तहत निजी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिये सरकारी या निजी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जा सकेंगी।
- यूपीसीएल के स्तर से राज्य के बाहर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जा सकेंगी। यह प्रावधान इसलिये किया गया है क्योंकि यूपीसीएल को अपनी खरीदी जाने वाली बिजली का एक निश्चित प्रतिशत सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट से खरीदना अनिवार्य है।
- नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के लिये रोज़गार की भी गारंटी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
- पॉलिसी में यह प्रावधान भी किया गया है कि यूपीसीएल सौर ऊर्जा का एक ग्रीन टैरिफ प्रस्ताव तैयार करेगा, जो कि नियामक आयोग को भेजा जाएगा। नियामक आयोग उपभोक्ताओं के लिये ग्रीन टैरिफ चुनने का विकल्प दे सकता है।
- इसके अलावा पीक आवर्स में ग्रिड में सौर ऊर्जा देने वालों को फीड इन टैरिफ से प्रोत्साहित कर सकता है। आसान पहुँच व निगरानी के लिये वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) और ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोट :

- नई पॉलिसी में उरेडा की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ाई गई हैं। इसके तहत उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सिंगल विंडो के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। उरेडा को लैंडबैंक बनाना होगा तथा सभी सरकारी ज़मीनें और भवनों की सूची बनानी होगी, जहाँ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लग सकते हैं। इसी प्रकार, ऐसी निजी भूमि भी चिन्हित करनी होंगी, जिन पर कोई प्राइवेट व्यक्ति लीज पर अपना प्रोजेक्ट लगा सके।
- नई नीति से मिलने वाले फायदे-
  - सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगेंगे।
  - लैंड यूज परिवर्तन शुल्क, न्यायालय शुल्क, पंजीकरण, भूमि उपयोग अनुमोदन, बाहरी विकास शुल्क, जाँच शुल्क और बुनियादी ढाँचा विकास शुल्क में छूट मिलेगी।
  - जो भी प्रोजेक्ट लगेगा, यूपीसीएल को अनिवार्य तौर पर उससे बिजली खरीदनी होगी। इससे निवेशकों का जोखिम कम होगा।
  - फीड इन टैरिफ के माध्यम से अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को मुआवज़ा मिलेगा। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास एवं स्वरोज़गार योजना को भी इससे लाभ पहुँचेगा।
  - अपने उपयोग के लिये और सामूहिक उपयोग के लिये निर्बाध अभिगम और एसजीएसटी व बिजली शुल्क में छूट मिलेगी।

चिन्यालीसौड़ में वायुसेना का तीन दिवसीय अभ्यास शुरू

चर्चा में क्यों ?

13 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत-चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का तीन दिवसीय अभ्यास शुरू हो गया।

प्रमुख बिंदु

- वायुसेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले अभ्यास में यहाँ वायुसेना के मल्टीपर्पज विमान एएन-32 की लैंडिंग और टेक-ऑफ का अभ्यास किया जाएगा। हालाँकि वायुसेना यहाँ पहले भी एएन-32 विमान की सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक-ऑफ करा चुकी है। यह इस साल का पहला अभ्यास है।
- गौरतलब है कि भारत-चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जनपद में चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना इस हवाई अड्डे को अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) बनाना चाहती है और समय-समय पर यहाँ अपने विमानों का अभ्यास करती है।
- उल्लेखनीय है कि वायुसेना के एएन-32 विमान का पूरा नाम एंटोनोव-32 है। इन्हें वायुसेना ने सोवियत यूनियन से खरीदा था। यह दो इंजन वाला सैन्य यातायात विमान है, जो 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और 14500 फीट की ऊँचाई तक उड़ान भर सकता है, जिसमें पायलट, को-पायलट, गनर, नेविगेटर व इंजीनियर सहित 5 क्रू मेंबर और 50 लोग सवार हो सकते हैं। जीपीएस से लैस इस विमान में रडार और मॉडर्न नेवीगेशन सिस्टम भी होता है।

उत्तराखंड बजट- 2023-2024

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश का वर्ष 2023-24 के लिये 77407.08 करोड़ का बजट पेश जिसमें रोज़गार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का इस वर्ष का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास से लिये जो भी प्राथमिकताएँ तय की हैं, उनकी झलक बजट में दिखाई देगी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के बजट में समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढाँचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए नीतिगत बदलाव व बजटीय प्रावधान किये गए हैं।
- सात बिंदुओं पर है बजट का फोकस-
  - मानव पूंजी में निवेश पर ज़ोर दिया गया है।
  - समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुँचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिये प्लेटफॉर्म देना।
  - स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा।
  - पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्द्धन एव संरक्षण।
  - निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
  - प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास।
  - इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन।
- वर्ष 2022-23 के बजट के महत्त्वपूर्ण बिंदु -
  - बजट में रोज़गार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है।
  - गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।
  - माध्यमिक विद्यालयों के लिये उत्कृष्ट कलस्टर के लिये 51 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  - उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिये 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  - उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिये दो करोड़ रुपए का प्रावधान।
  - मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिये 11 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  - लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिये 50 हज़ार रुपए।
  - भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
  - NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया है।
  - बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।
  - पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिये एक करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान।
  - 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम।
  - जी-20 के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  - बालिका साइकिल योजना के लिये 15 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  - स्वरोज़गार योजना के लिये 40 हज़ार करोड़ का प्रावधान।

नोट :

चमोली की मानसी नेगी ने 20 किमी. वॉक रेस में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यो ?

हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चमोली ज़िले के मजोठी गाँव की मानसी नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 किमी. वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर मानसी नेगी ने इस रेस को एक घंटे 41 मिनट में पूरा करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाई और स्वर्ण पदक हासिल किया।
- विदित है कि मानसी नेगी ने पिछले साल गुवाहाटी में 11 से 15 नवंबर तक आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर-20 महिला वर्ग की 10 हज़ार मीटर की वॉक रेस में 47:30:94 मिनट के नए नेशनल मीट रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था।
- मानसी के कोच अनूप बिष्ट ने बताया कि मानसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज एक्सीलेंट विंग की खिलाड़ी है। मानसी सीमांत जनपद चमोली के मजोठी गाँव की रहने वाली है। मानसी के पिता लखपत सिंह नेगी की 2016 में मृत्यु हो गई थी।

नोट :

उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

17 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिये सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इसमें पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिये प्रोजेक्ट लागत की न्यूतनम सीमा पाँच करोड़ रुपए की गई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की नई पर्यटन नीति से निवेश को बढ़ावा देने के लिये नए पर्यटक स्थल विकसित किये जाएंगे। पर्यटन निवेश हेतु बनाई गई नीति के अंतर्गत प्रदेश के शहरों को तीन श्रेणियों में अलग किया गया है। इनमें पर्यटन की दृष्टि से अनछुए स्थलों पर निवेश करने पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
- इसके अलावा हेली टूरिज्म, कैरावान टूरिज्म, एडवेंचर, कैब ऑपरेटर (इलेक्ट्रिक वाहन) में निवेश पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोज़गार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
- ये हैं शहरों की तीन श्रेणियाँ -
  - श्रेणी-ए: हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर, देहरादून, रानीखेत, अल्मोड़ा तहसील।
  - श्रेणी-बी: ज़िला अल्मोड़ा शेष क्षेत्र, देहरादून ज़िले की कालसी, चकराता और त्यूनी तहसील, बागेश्वर का गरुड़, पौड़ी ज़िले का कोटद्वार, लैंसडौन, यमकेश्वर और धूमाकोट तहसील, टिहरी गढ़वाल की धनौल्टी और नरेंद्रनगर तहसील।
  - श्रेणी-सी: उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर ज़िले का शेष क्षेत्र, पौड़ी और टिहरी ज़िले के वे शेष क्षेत्र जो श्रेणी-बी में शामिल नहीं हैं।
- सरकार नई नीति के तहत श्रेणी के आधार पर पूंजी निवेश पर अनुदान देगी। इसमें श्रेणी-ए क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अनुदान, श्रेणी-बी में चयनित क्षेत्रों में 35 फीसदी और श्रेणी-सी के क्षेत्रों के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
- पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा, मार्केटिंग प्रमोशन, कौशल प्रशिक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित के लिये हेली पर्यटन के लिये आकर्षक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया।
- हिलीयम, हॉट एयर बैलून, बिलिंप्स, कैब ऑपरेटर, हेलीकॉप्टर, वाटर प्लेन, कैरावान, मोटर हाउस, क्रूज बोट, हाउस बोट, क्रीड़ा नौका, एडवेंचर के लिये ट्रेकिंग, रॉक क्लाइबिंग, वाटर स्पोर्ट्स, वोट रेस, स्केटिंग, फिशिंग, एयरो स्पोर्ट्स, रोप-वे, कम से कम 15 कमरों का होटल और रिजॉर्ट, फ्लोटिंग रिजॉर्ट, हैरिटेज होटल, होटल एंड मोटल, स्पा हेल्थ रिजॉर्ट, वेलनेस रिजॉर्ट, टूरिस्ट रिजॉर्ट, आर्ट गैलरी, एन्यूमेंट पार्क आदि में निवेश करने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

परमजीत ने रेस वॉक में ओलंपिक 2024 के लिये किया क्वालीफाई

चर्चा में क्यों ?

19 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के चमोली जनपद के बैरागना स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक गोपाल बिष्ट ने बताया कि परमजीत सिंह बिष्ट ने जापान में आयोजित एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में नवाँ स्थान प्राप्त करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये क्वालीफाई किया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि परमजीत सिंह बिष्ट ने जापान में आयोजित एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में 1 घंटा 20 मिनट और 6 सेकंड के साथ 9वाँ स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये क्वालीफाई किया है।
- इससे पहले उत्तराखंड के चमोली ज़िले की एथलीट मानसी नेगी ने तमिलनाडु में हुई 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 घंटा 41 मिनट समय के साथ 20 किमी. वॉक रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है।

नोट :

- विदित है कि प्रदेश के चमोली जनपद की मंडल घाटी के खल्ला गाँव निवासी परमजीत सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना के पूर्व छात्र हैं। मौजूदा समय में परमजीत खेल कोटे से भारतीय सेना (नेवी) में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
- व्यायाम शिक्षक गोपाल बिष्ट ने बताया कि मनीष रावत के बाद परमजीत जनपद का दूसरा खिलाड़ी है जो ओलंपिक के लिये क्वालीफाई हुआ है।
- ज्ञातव्य है कि मनीष ने 2016 में रियो में आयोजित ओलंपिक में प्रतिभाग किया था।

उत्तराखंड में द्रोणाचार्य, खेल रत्न और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के लिये नाम तय

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि राज्य के वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिये तीन खेल प्रशिक्षकों को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवॉर्ड और तीन खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार सहित कुछ अन्य पुरस्कारों के लिये चयनित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- खेल निदेशक जितेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि शासन की हाईपावर कमेटी और खेल मंत्री के अनुमोदन के बाद पुरस्कारों के लिये नाम घोषित कर दिये जाएंगे।
- खेल विभाग की ओर से 24 मार्च को परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि राज्य के खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट के मैदान से लेकर बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों में देश और दुनियाभर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन पिछले चार साल से कोविड एवं अन्य कई वजहों से राज्य के खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार नहीं मिल पाए थे। हालाँकि विभाग की ओर से समय-समय पर इसके लिये आवेदन मांगे गए, लेकिन खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों के नाम फाइनल नहीं हो पाए।
- खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक द्रोणाचार्य अवार्ड के लिये विभाग को आठ और खेल रत्न पुरस्कार के लिये 11 आवेदन मिले, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिये छह आवेदन मिले हैं।

नोट :

- द्रोणाचार्य, खेल रत्न एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिये खिलाड़ियों एवं खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार मिलने का इंतजार खत्म होने जा रहा है, लेकिन हिमालय पुत्र पुरस्कार के लिये खिलाड़ियों को अभी इंतजार करना होगा। वर्ष 2022 में शासनादेश होने के बावजूद विभाग की ओर से अभी इसके लिये आवेदन नहीं मांगा गया है।

उत्तराखंड कैबिनेट ने आबकारी नीति 2023-24 को दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिये आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दाम पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस सस्पेंड होंगे। अगर किसी दुकान की पाँच बार एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत आई तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
- बैठक में तय किया गया कि देशी मदिरा के पव्वे काँच के बजाए अब टेट्रा पैक में मिलेंगें ताकि मिलावट रोकी जा सके।
- सरकार ने डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस का शुल्क पहाड़ों में आठ लाख रुपए और मैदानी ज़िलों में आठ से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है।
- नई आबकारी नीति में बार रेस्टोरेंट के शुल्क में कोई इज़ाफा नहीं किया गया है। ये निकटवर्ती शराब ठेके से ही ले सकेंगे। समुद्र आयतित मदिरा की कीमतों को भी नियंत्रित किया गया है।
- राज्य में डिपार्टमेंटल स्टोर अब अपने ज़िले में स्थित शराब ठेके से ही शराब ले सकेंगे, जिससे उनकी मनमानी पर लगाम लगेगी।
- नई नीति में दैवीय आपदा या धरना प्रदर्शन के दौरान बंद रहने वाली दुकानों का ज़िलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उस अवधि का राजस्व माफ करने का प्रावधान किया गया है।
- नई नीति के बाद प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शराब की कीमतों के अंतर को 150 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है।
- नई आबकारी नीति को मंजूरी के बाद एक अप्रैल से देशी-विदेशी शराब के दाम 100 रुपए से 300 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे।
- आबकारी नीति 2023-24 के तहत 3 रुपए प्रति बोतल उपकर के रूप में लिया जाएगा, जो राज्य में गौ रक्षा, खेल और महिला कल्याण के लिये निर्धारित किया जाएगा।
- वर्ष 2023-24 के लिये आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री ने किया देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च, 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े 4-मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के उद्घाटन की यह ऐतिहासिक घटना अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के रहस्यों का अध्ययन करने और शेष विश्व के साथ इसे साझा करने के लिये भारत को क्षमताओं के एक अलग और उच्च स्तर पर रखती है।

नोट :

- आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज- एआरईईएस) ने घोषणा की कि विश्व स्तरीय 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (आईएमएलटी) अब सुदूर एवं गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिये तैयार है। इसने मई 2022 के दूसरे सप्ताह में अपना पहला प्रकाश प्राप्त किया।
- यह दूरदर्शी (टेलीस्कोप) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान, एआरईईएस उत्तराखंड (भारत) के नैनीताल ज़िले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि आईएमएलटी के सहयोग में भारत के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एआरईईएस), बेल्जियम के लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड की पॉज्नान वेधशाला, उज्बेक विज्ञान अकादमी के उलुग बेग खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, लवल विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और कनाडा में विक्टोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ता शामिल हैं।
- इस टेलिस्कोप को एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम्स (एएमओएस) कॉर्पोरेशन और बेल्जियम में सेंटर स्पैटियल डी लीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था।
- उन्होंने बताया कि यह आईएलएमटी प्रकाश को एकत्र एवं घनीभूत करके केंद्रित करने के लिये तरल पारे की एक पतली परत से बने 4 मीटर व्यास के घूमने वाले दर्पण का उपयोग करता है। धात्विक पारा (मर्करी) कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है और साथ ही अत्यधिक परावर्तक भी होता है और इसलिये, यह ऐसा दर्पण बनाने के लिये आदर्श रूप से अनुकूल है।
- गौरतलब है कि आईएलएमटी पहला ऐसा तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिये डिजाइन किया गया है और यह वर्तमान में देश में उपलब्ध सबसे बड़ा एपर्चर टेलीस्कोप है साथ ही यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है।
- आईएलएमटी को हर रात इसके ऊपर से गुजरने वाली आकाश की पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिये डिजाइन किया गया है, जिससे सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनीय आकाशीय वस्तुओं का पता लगाने में सहायता मिलती है।
- हर रात आकाश की पट्टी को स्कैन करते समय यह टेलीस्कोप लगभग 10-15 गीगाबाइट डेटा उत्पन्न करेगा और जिसे आईएलएमटी द्वारा उत्पन्न डेटा बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) /मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) एल्गोरिदम के अनुप्रयोग की सुविधा देने के साथ ही आईएमएलटी के साथ देखी गई वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिये प्रयोग किया जाएगा।
- मंत्री ने बताया कि चर और क्षणिक तारकीय स्रोतों को खोजने और पहचानने के लिये डेटा का तेजी से विश्लेषण किया जाएगा। 6 मीटर का डीओटी, परिष्कृत बैक-एंड उपकरणों की उपलब्धता के साथ, आसन्न आईएलएमटी के साथ नवीनतम खोजे गए क्षणिक स्रोतों के तेजी से अनुवर्ती अवलोकन की अनुमति देगा।
- इसके अलावा आईएलएमटी से एकत्र किये गए डेटा, अगले 5 वर्षों के परिचालन समय में एक गहन फोटोमेट्रिक और एस्ट्रोमेट्रिक परिवर्तनशीलता सर्वेक्षण करने के लिये आदर्श रूप से अनुकूल होंगे।
- विदित है कि एक तरल दर्पण टेलीस्कोप में मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं- पहला, एक परावर्तक तरल धातु (अनिवार्य रूप से पारा) युक्त एक कटोरा सदृश पात्र दूसरा, एक एयर बियरिंग (अथवा मोटर) जिस पर तरल दर्पण स्थापित किया गया है और तीसरा, एक चलन प्रणाली (ड्राइव सिस्टम)। लिक्विड मिरर टेलिस्कोप इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि एक घूर्णन तरल की सतह स्वाभाविक रूप से एक परवलयिक (पैराबोलिक) आकार लेती है और जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिये आदर्श है।
- माइलर की एक वैज्ञानिक ग्रेड पतली पारदर्शी फिल्म पारे को वायु प्रवाह से बचाती है। परावर्तित प्रकाश एक परिष्कृत बहु-लेंस ऑप्टिकल सुधारक (करेक्टर) के माध्यम से गुज़रता है जो दृश्य के विस्तृत क्षेत्र में उत्कृष्ट छवियाँ उत्पन्न करता है। साथ ही फोकस पर दर्पण के ऊपर स्थित एक 4के 4के सीसीडी कैमरा, आकाश की 22 आर्कमिनट चौड़ी पट्टियों को रिकॉर्ड करता है।

सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक

चर्चा में क्यों ?

22 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) की ओर से आयोजित कार्यशाला में ऊटीमाको कंपनी के सीईओ रोनेन डैनियल ने सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर अपना प्रस्तीतुकरण देते हुए बताया कि आपदा के समय में यह तकनीक न्यूनतम समय में लोगों को अलर्ट कर देती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- संभावित आपदाओं से घिरे उत्तराखंड राज्य के लिये सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक कारगर सिद्ध हो सकती है। इसके माध्यम से बादल फटने, बिजली गिरने, हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी आपदाओं के बाद होने वाले वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह तकनीक आपदा की स्थिति में मोबाइल फोन के ज़रिए लोगों को अलर्ट कर देती है।
- ऐसी स्थिति में संभावित आपदा क्षेत्र में जितने भी मोबाइल मौजूद होंगे, वह स्वत: बजने लगेंगे, भले ही उस इलाके का नेटवर्क ठप हो गया हो।
- सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक प्रणाली सीएमएएस अलर्ट का प्रसार करने में सक्षम है, जो चेतावनी जारी करने का विश्व में सबसे बेहतर मानक है।
- ऊटीमाको कंपनी के सीईओ रोनेन डैनियल ने बताया कि सीएमएएस अलर्ट से पहले मोबाइल पर ज़ोर से बीपिंग ध्वनि, अलार्म टोन में लगातार कंपन होता है और पॉप-अप मैसेज आता है, जो तब तक बंद नहीं होता, जब तक कि संबंधित व्यक्ति उसे स्वयं बंद नहीं करता। इसकी क्षमता कुछ ही मिनट के भीतर लाखों लोगों को सचेत करने की है। इस तकनीक के माध्यम से मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी भी जारी की जाती है।
- विदित है कि जापान, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, कोरिया, नीदरलैंड, यूरोपीय संघ जैसे दुनिया के तमाम देश आज इस तकनीक को अपना रहे हैं। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य ने इस तकनीक को अपनाया है, जहाँ सुनामी और चक्रवात आने का खतरा बना रहता है।
- सेल ब्रॉडकास्ट की मुख्य विशेषताएँ -
  - रीयल टाइम और स्थान-आधारित अलर्ट।
  - मोबाइल नंबरों की आवश्यकता नहीं है। एसएमएस के विपरीत कुछ सेकंड में दस लाख लोगों तक पहुँच सकता है।
  - सब्सक्राइबर की निजता संबंधी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सेल ब्रॉडकास्ट को प्रसार के लिये मोबाइल नंबरों की आवश्यकता नहीं है।
  - नेटवर्क जाम होने पर भी काम करता है (सांप्रदायिक दंगों के भड़कने आदि के दौरान प्रभावी)।
  - डेटा की आवश्यकता नहीं है, एक साथ कई भाषाओं में काम करता है।
  - सभी आपातकालीन मानकों का पालन करता है।

नोट :

'रेट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक'

चर्चा में क्यों ?

22 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन विभाग की ओर से वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये आयोजित कार्यशाला में देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के मेकेनिकल क्लस्टर द्वारा तैयार की गई 'रेट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक'को पेश किया गया, जो 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को नई जिंदगी देगी।

प्रमुख बिंदु

- यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के प्रो. डॉ. अजय कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी की इंजन लेबोरेटरी के अनुसार 'रेट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक'में डीजल वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से बीएस-6 की तरह वाहन कम प्रदूषण उत्सर्जित करेंगे।
- इस तकनीक से उम्र पूरी कर चुके डीजल वाहनों को नई जिंदगी मिल सकती है और उन्हें फिर से सड़कों पर दौड़ने लायक बनाया जा सकता है।
- पुराने वाहनों में डीजल जलने के बाद उससे निकलने वाली जहरीली गैस वायुमंडल में जाकर प्रदूषण फैलाती है। इसे साफ करने के लिये इस तकनीक में विशेष फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है।
- 'रेट्रोफिट सॉल्यूशन तकनीक'में डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का फिल्टर है। यह कार्बन मोनो ऑक्साइड को कार्बन डाई ऑक्साइड में बदल देता है। धुएँ में शामिल सूक्ष्म कण डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (डीपीएफ) में फंस जाते हैं। इन कणों को जलाने के लिये माइक्रोवेव्स ओवन का प्रयोग किया जाता है।
- इससे निकलने वाली किरणें सूक्ष्म कणों को जला देती हैं। इसके बाद इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और फिल्टर साफ हो जाता है। इसमें सिलेक्टिव केटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) फिल्टर का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड अमोनिया के प्रयोग से जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में बदल दिया जाता है। इससे वायु प्रदूषण करने वाले प्रमुख तत्त्वों को उत्सर्जित होने से रोक दिया जाता है।
- यूनिवर्सिटी की इंजन लेबोरेटरी के अनुसार इस तकनीक से डीजल वाहनों के धुएँ में शामिल 60 प्रतिशत तक बिना जले कार्बन को जला दिया जाता है। वहीं, 29 प्रतिशत कार्बन मोनो ऑक्साइड को कार्बन डाई ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इस तकनीक से 91 प्रतिशत तक सूक्ष्म कण जलाकर खत्म कर दिये जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि 2020 में इस तकनीक को बनाया गया। इसे पेटेंट कराने के लिये आवेदन किया गया है। कई चरणों में टेस्टिंग के बाद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस तकनीक के ज़रिए वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को बीएस-6 वाहनों की तरह न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री ने की कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिये कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रदेश में 'मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना'लागू कि गई है जिसके अंतर्गत राज्य के प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज़ की बसों में 50 फीसदी किराया ही देना होगा। यह सुविधा परीक्षा देने जाने और वापस आने, दोनों तरफ की यात्रा के लिये मिलेगी।
- राज्य में अब कक्षा छह से ही कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा लागू हो जाएगी। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर उनको मिलने वाला पेंशन विधवा पत्नी को दी जाएगी।
- इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग की एक साल नई मिसाल विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया।

नोट :

- उन्होंने 37 करोड़ रुपए की लागत से सहस्त्रधारा के तरला नागर में प्रस्तावित सिटी फॉरेस्ट योजना का भी शिलान्यास किया।
- सीएम धामी की अन्य घोषणाएँ-
  - चलती-फिरती प्रयोगशाला - उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिये सभी 13 ज़िलों में चलती-फिरती प्रयोगशाला (लैब ऑन व्हील्स) शुरू की जाएगी।
  - सांइस व आईटी कॉरिडोर - राज्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी गलियारा (कॉरिडोर) बनेगा। जल्द सांइस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आएगी।
  - खेल विश्वविद्यालय - हल्द्वानी स्थित गौलापार में बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उच्चीकरण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
  - मुख्यमंत्री औद्यानिकी योजना - प्रदेश के किसानों के लिये मुख्यमंत्री औद्यानिकी योजना शुरू की जाएगी। वहीं पशुपालकों के लिये मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन शुरू होगा।
  - सड़कों से जुड़ेंगे गाँव - जल्द मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत 250 से अधिक आबादी वाले गाँवों की मुख्य सड़कों का निर्माण होगा।
  - कौशल विकास योजना - युवाओं के लिये मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोज़गार योजना शुरू होगी। इसमें स्नातक पास छात्रों को आवश्यक रूप से दक्ष बनाया जाएगा।
  - सरोवर योजना - सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इन्हें पर्यटक स्थल व जल क्रीड़ा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - स्वरोज़गार केंद्र - सभी ज़िलों में ज़िला सेवा योजना एवं कौशल विकास कार्यालय को स्वरोज़गार केंद्र के नोडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - चलते-फिरते स्कूल - श्रमिकों के बच्चों को साक्षर बनाने के लिये चलते फिरते (मोबाइल) स्कूल शुरू किये जाएंगे, जिनमें शिक्षक मौके पर जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे।
  - गैरसैंण तक चौड़ा होगा मार्ग - ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिये दिवालीखाल से सड़क मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कर्णप्रयाग गैरसैंण मार्ग सुगम हो जाएगा।
  - लोक पर्वों को महत्त्व - उत्तरायणी, फूलदेई, हरेला, ईगास, बूढ़ी दिवाली जैसे उत्तराखंड के लोकपर्वों को व्यापक पहचान दिलाए जाने के लिये समेकित नीति बनेगी।

जल जीवन मिशन के लिये प्रदेश को मिले 403 करोड़

चर्चा में क्यों ?

22 मार्च, 2023 को उत्तराखंड पेयजल निगम के एमडी उदयराज सिंह ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल की 'जल जीवन मिशन' योजना के लिये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य को 403 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 14 लाख 94 हज़ार 375 घरों में नल से जल पहुँचाने की योजना है।
- इस मिशन के तहत प्रदेश के अभी तक 9 लाख 95 हज़ार 477 घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है।
- जल जीवन मिशन के तहत 17 हज़ार से अधिक छोटी-बड़ी परियोजनाएँ बनाई गई हैं, जिनके लिये जल शक्ति मंत्रालय अभी तक दो किश्तों के रूप में करीब 800 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर चुका है।
- पेयजल निगम के एमडी उदयराज सिंह ने बताया कि तीसरी किश्त से इस वित्तीय वर्ष के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में भी कार्य होंगे। इससे मिशन के कार्यों में तेजी आएगी।
- जल जीवन मिशन के तहत वैसे तो राज्य में करीब 72 प्रतिशत घरों तक हर घर नल से जल पहुँचाया जा चुका है लेकिन रफ्तार अपेक्षाकृत कम है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने प्रदान किये उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

24 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में राज्य की खेल प्रतिभाओं को वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिये देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों से पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित छह खेल प्रतिभाओं को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया।
- इसके अलावा वर्ष 2021 और 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों व 42 प्रशिक्षकों को दो करोड़ से अधिक के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- इस अवसर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये सरकार ने सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
- राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति व चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिये प्रतिबद्ध है। आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का आदेश होने से ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी सीधे डीएसपी व सहायक निदेशक बन सकेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर पुरस्कार की धनराशि 30 से 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।
- राज्य में नई खेल नीति बनाई गई है, जिसमें पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है।
- इन्हें मिला पुरस्कार -
  - देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार - वर्ष 2019-20 के लिये बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, वर्ष 2020-21 के लिये एथलीट चंदन सिंह।
  - देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार - वर्ष 2019-20 के लिये बैडमिंटन प्रशिक्षक धीरेंद्र कुमार सेन, वर्ष 2020-21 के लिये ताईक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी, वर्ष 2021-22 के लिये तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान।
  - लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड - वर्ष 2021-22 का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुरेश चंद्र पांडे को एथलेटिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया गया।

नोट :

पहली बार यात्रा मार्गों पर लगेंगे 50 हेल्थ एटीएम

चर्चा में क्यों ?

26 मार्च, 2023 को उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये पहली बार यात्रा मार्गों पर 50 हेल्थ एटीएम लगाए जाने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग और हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज (एचपीई) के बीच एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम लगाए जाने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।
- हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज के निदेशक अंकुर मल्होत्रा ने बताया कि सीएसआर के तहत चारधाम यात्रा के लिये हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें 70 से अधिक जाँच की जा सकती हैं।
- जाँच के साथ ही हेल्थ एटीएम से टेली मेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया जा सकेगा। हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज की ओर से 24 घंटे ये सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- आगामी तीन माह तक कंपनी के इंजीनियरों की ओर से हेल्थ एटीएम की देखरेख की जाएगी। 24 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि मानसखंड स्थित पवित्र स्थानों मानसरोवर यात्रा, बैजनाथ धाम, कैंची धाम, पूर्णागिरी, चितई धाम के लिये भी हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज से हेल्थ एटीएम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। केदारखंड की तर्ज पर मानसखंड के लिये भी सीएसआर के तहत हेल्थ एटीएम मेडिकल कियोस्क मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी।
- चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ न हो, इसके लिये स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है।

उत्तराखंड में जल्द ही गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेंटिग होम की सुविधा

चर्चा में क्यों ?

25 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व बर्थ वेटिंग होम की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- बर्थ वेटिंग होम की सुविधा प्रदेश के सभी 13 जनपदों में स्थापित वन स्टॉप सेंटर व कामकाजी महिला छात्रावास में की जाएगी।
- राज्य में 1 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिये सीमांत ज़िला पिथौरागढ़ में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को भर्ती कर मानकों के अनुसार पोषण चिकित्सा की देखभाल प्रदान की जाएगी।
- स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के लिये 150 करोड़ की बजट की मंजूरी दी है।
- योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय देखभाल समय पर प्राप्त होगी। साथ ही प्रसव से पूर्व गर्भवती महिलाओं को सहूलियत होगी। होम डिलीवरी को संस्थागत प्रसव में प्रोत्साहित करने के लिये पर्वतीय जनपदों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेटिंग होम का इस्तेमाल किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल ज़िले में मोबाइल टीबी वैन शुरू की जाएगी, जिसमें जाँच के लिये एक्सरे व टूनेट मशीन स्थापित होंगी।
- अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी को मोबाइल एक्सरे के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट में सहमति दी गई। इससे टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग करने में आसानी होगी। मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग के लिये टिहरी व पिथौरागढ़ ज़िले में

नोट :

मोबाइल वेन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति मिली है।

- एएनएम और सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चमोली ज़िले में एनएचएम ऑफिस एवं प्रशिक्षण हॉल की स्वीकृति दी गई है।
- मरीजों को पर्ची बनाने के लिये लंबी कतार से छुटकारा देने के लिये 14 अस्पतालों में कतार प्रबंधन व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें मरीजों को टोकन दिया जाएगा, जिससे उन्हें लाइन में खड़ा न होना पड़े। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भूपतवाला में खाली पदों को एनएनएम के माध्यम से भरा जाएगा।

प्रदेश में आभा आईडी बनाने में देहरादून ज़िला अव्वल

चर्चा में क्यों ?

25 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) बनाने में देहरादून ज़िला अव्वल है।

प्रमुख बिंदु

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य मिशन निदेशक एवं अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश के 30.61 लाख से अधिक लोग अपनी आभा आईडी बनाकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। आईडी बनाने वाले लोगों का स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण ब्योरा ऑनलाइन दर्ज हो चुका है।
- प्रदेश की राजधानी देहरादून में सबसे अधिक 6,61,919 आभा आईडी बनी हैं, जबकि नैनीताल ज़िला दूसरे स्थान पर है।
- ज्ञातव्य है कि प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। मिशन की ओर से किये गए प्रयासों से प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटाइज करने की गति अपेक्षाओं के अनुरूप है।
- विदित है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मिशन के तहत हर व्यक्ति की आभा आईडी बनाई जानी है। आईडी बनाने से स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
- आभा आईडी के फायदे -
- स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
- अस्पताल के पंजीकरण से लेकर उपचार तक पेपरलेस होगा।
- अस्पताल में क्यूआर कोड के ज़रिये टोकन लेने की सुविधा।
- बीमारी के इलाज से संबंधित रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रहेगा।
- राज्य में आभा आईडी का जनपदवार विवरण –

ज़िला	आभा आईडी
देहरादून	661919
नैनीताल	398571
हरिद्वार	282253
ऊधमसिंह नगर	232694
पौड़ी गढ़वाल	183236
अल्मोड़ा	143166
टिहरी	122741
पिथौरागढ़	94285
चमोली	75008
बागेश्वर	71453
चंपावत	65452

नोट :

उत्तरकाशी	55736
रुद्रप्रयाग	28832
ज़िले की सूचना न देने वाले	646288

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक क्रांतिकारी कदम है। आभा नंबर के माध्यम से स्वास्थ्य की सभी जानकारी मिल सकेगी। प्रदेश में शत-प्रतिशत लोगों को मिशन से जोड़ने के काम को प्राथमिकता से करने के लिये संबंधित अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिये गए हैं।

उत्तराखंड में पेपरलेस होगी विधानसभा

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 को देहरादून स्थित विधानसभा भवन कार्यालय कक्ष में स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने विधायकों व सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अफसरों संग हुई बैठक में बताया कि प्रदेश में गोवा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जल्द ई-विधानसभा बनाई जाएगी, जिससे विधानसभा का सत्र पेपरलेस होगा।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फोरम से ई-विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों का समावेश करना आसान होगा। विधायकों के अलावा आम जनता भी प्रक्रिया में भाग ले सकेगी और सब अपनी राय रख दे सकेगी।
- ई-विधानसभा बनाने से कागज़ों की बचत होगी। विधानसभा कार्यों में बहुत से दस्तावेज़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे काफी खर्चा आता है, लेकिन ई-विधानसभा के माध्यम से दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे कागज़ों की बचत हो सकती है।
- इसके अलावा ई-विधानसभा के माध्यम से दस्तावेज़ों को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। कम कागज़ों के उपयोग से पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है।
- ई-विधानसभा बनने से उत्तराखंड के गठन से अभी तक के जितने भी विधानसभा सदन चले हैं, की पूरी जानकारी भी एक जगह डिजिटल संग्रहित की जाएगी।
- विदित है कि हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में ई-विधानसभा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक का अध्ययन कर लिया गया है, जिसकी तर्ज पर उत्तराखंड विधानसभा को भी ई-विधानसभा बनाया जाएगा।

नोट :

जी-20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक रामनगर में आयोजित हुई

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को जी-20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (जी-20 सीएसएआर) की पहली बैठक रामनगर, उत्तराखंड में आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि जी-20 सीएसएआर, भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कर रहा है।
- एक दिवसीय गोलमेज बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा हुई-
  - 'बेहतर रोग नियंत्रण और महामारी की बेहतर तैयारी के लिये 'वन हेल्थ में अवसर' विषय के तहत, महामारी को ध्यान में रखते हुए सशक्त, अनुकूल और समय पर कार्रवाई के लिये महामारी से जुड़ी तैयारी की योजना; मनुष्यों, पशुधन और वन्य जीवन के लिये एकीकृत रोग निगरानी तंत्र, वन हेल्थ के रोगों के लिये अनुसंधान एवं विकास का रोडमैप तथा विश्लेषण में निवेश (जैसे रोग मॉडलिंग, एआई/एमएल उपकरण) और डेटा मानक आदि पर चर्चा हुई।
  - 'विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुँच का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय' विषय के तहत, नि:शुल्क, तत्काल और सार्वभौमिक पहुँच सुविधा; पत्रिकाओं को ग्राहक शुल्क और उनके द्वारा लगाए जाने वाले निबंध प्रसंस्करण शुल्क को कम करना; अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान-भंडार/अभिलेखागार के साथ राष्ट्रीय ज्ञान-भंडार के लिये परस्पर संचालित लिंक की स्थापना और सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक अनुसंधान के ज्ञान आउटपुट को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिये खुली पहुँच का कार्यादेश आदि पर चर्चा की गई।
  - 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) में विविधता, समानता, समावेश और पहुँच की सुविधा'विषय के तहत भाग लेने वाले देशों ने बड़े वैज्ञानिक उद्यम तक कम-प्रतिनिधित्व प्राप्त, कम-विशेषाधिकार प्राप्त, वंचित, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ जनजातीय/मूल समुदायों की पहुँच को सुविधाजनक बनाने के अपने प्रयासों को साझा किया। सत्र में वैज्ञानिक सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली (टीकेएस) को ज्ञान की औपचारिक प्रणाली में शामिल करना और भाषा विविधता की क्षमता की पहचान करना एवं वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुँच में आने वाली बाधाओं को दूर करना आदि पर भी चर्चा की गई।
  - चौथे सत्र में समावेशी, सतत् और कार्य-उन्मुख वैश्विक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति संवाद के लिये एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा हुई।

नोट :

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस) का कंप्यूटरीकरण सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्रों और जनऔषधि केंद्रों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार 30 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ और आज राज्य के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
- उत्तराखंड में 95 एमपीएसीएस की स्थापना का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के तहत 95 जन औषधि केंद्र और जन सुविधा केंद्र शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
- केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'सहकार से समृद्धि' की कल्पना के साथ एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। मंत्रालय के माध्यम से देश में सभी 65,000 सक्रिय पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण शुरू हो गया है। 307 जिला सहकारी बैंकों सहित कई सुविधाओं का भी कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। आज 307 सहकारी बैंक शाखाओं और 670 एमपीएसीएस का कंप्यूटरीकरण पूरा कर उत्तराखंड सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण से व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आएगी और ऑनलाइन ऑडिट होगा, जिससे पैक्स के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। 95 जन सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं को सीधे गाँवों तक पहुँचाएंगे। सहकारी जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को लगभग 50 से 90 प्रतिशत सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी।
- केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री शाह ने उत्तराखंड के 95 विकासखंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती के मॉडल का भी शुभारंभ किया।
- सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है, बीज, जैविक खेती के विपणन और किसानों की उपज के निर्यात के लिये बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीज, जैविक खेती के विपणन और कृषकों के उत्पाद के निर्यात के लिये बहुराज्य सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं।

नोट :

- उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नल से जल (नल से पानी) योजना पैक्स को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा भेजे गए बहुआयामी पैक्स के आदर्श उपनियमों में पैक्स गाँव को पानी उपलब्ध कराने में भी सक्षम होंगे।

The Vision

नोट :